दैनिक जागरण, भोपाल
14 FEB 2011

प्रशंसनीय पहल और अद्भुत परम्परा

मुख्यमंत्री श्री चौहान के उपवास और स्थगन के कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं **रमेश शर्मा**

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान किसानों की पीड़ा और मध्यप्रदेश के अन्य विकासात्मक बिन्दुओं पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये 13 फरवरी की पूर्वान्ह उपवास पर बैठने वाले थे। किंतु दो घंटे पूर्व उन्होंने अपना उपवास स्थगित कर दिया। उन्हें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने फोन पर उपवास त्यागने का आग्रह किया। संबंधित सभी विषयों पर बातचीत के लिये बीस फरवरी को दिल्ली आमंत्रित किया और आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश के हितों की अनदेखी नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह ने प्रधानमंत्री की बात को स्वीकारा और अपना उपवास फिलहाल स्थगित कर दिया। इस समूचे घटनाक्रम में एक समन्वयक के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही जिन्होंने पहले केन्द्र सरकार से और फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान से बात की। बहुत दिनों बाद भारत में संविधान की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक सकारात्मक पहल, समन्वय, सम्मान और पुर्नप्रतिष्ठा का पक्ष सामने आया।

प्रजातंत्र में संघीय व्यवस्था के बावजूद विभिन्न राजनैतिक विचारों में एक स्पर्धा होती है। स्पर्धा में आगे निकलना ही सफलता का सूचक होता है और यदि राजनैत्रिक स्पर्धा का अभीष्ठ सत्ता हो तो स्वयं की छवि बनाने के साथ-साथ स्पर्धी की छवि बिगाड़ना भी जरूरी होता है। स्वतंत्रता के बाद के इन बासठ वर्षों के राजनैतिक जीवन में यही सब सामने आया है। इसमें कोई किसी से कम नहीं, अपवाद नहीं। इसी स्पर्धा और स्पर्धा की रणनीति के अंतर्गत ही लोकतंत्र का मान अनेक बार दंडित हुआ है, कमजोर हुआ है। स्पर्धा यदि जीत के लिये हो तब सत्य, सिद्धांत या सम्मान का ह्रास होना लाजमी होता है। इसकी पुर्नप्रतिष्ठा की न तो किसी को परवाह होती है और न कोई प्रयत्न करता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि परवाह भी हुई, प्रयत्न भी हुआ और सम्मान भी हुआ जिसने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का कद तो बढ़ाया ही है साथ ही देश के संविधान में वर्णित संघीय स्वरूप को भी प्रतिष्ठा दी। मध्यप्रदेश में किसानों की पीड़ा किसी से छिपी नहीं है। एक तो किसान कृषि के लागत मूल्य बढ़ने से पहले ही परेशान हैं उस पर पाला ने उन्हें बरबाद करके रख दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का इस दर्द से दुःखी होना स्वाभाविक था। इसलिये नहीं कि वे एक मुख्यमंत्री हैं बल्कि इसलिये ज्यादा कि वे स्वयं किसान और किसान के बेटे हैं। उन्होंने अपने हाथ से हल चलाया है। खून को पसीने में बदलकर जवान किसान खेत जोतता है तब उसकी खुशी और दर्द फसल की संभावना में ही निहित होते हैं। यही कारण था कि विदिशा जिले के गांव तैयबपुर-हैदरगढ़ में पाले से पिटी फसल को देखते ही श्री शिवराजसिंह चौहान के आंसू निकल पड़े। तब उन्होंने भोपाल लौटते ही अधिकारियों को तलब किया। नुकसान का आकलन किया और दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से राहत के लिये प्रार्थना की। जैसा होता है इस बार भी पूर्व वर्षों की भाँति दिल्ली से तुरंत सहायता न आ सकी। श्री चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपना खाजाना खोला, किसानों को तत्कालिक आर्थिक सहायर्ता प्रदान की फिर भी केन्द्र की सहायता के अभाव में उतनी मदद न हो सकी जितनी राज्य सरकार और किसानों को दरकार थी। इस विलंब ने शिवराजसिंह चौहान को पीड़ित किया और उन्होंने उपवास की घोषणा कर दी।

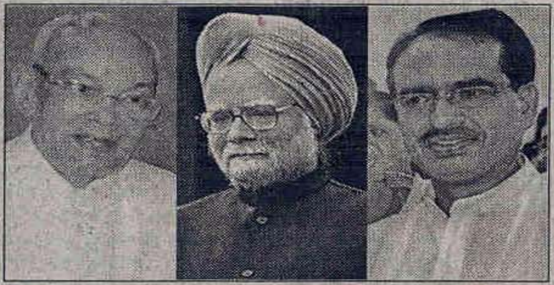

ऐसा पहली बार हुआ है कि परवाह भी हुई, प्रयत्न भी हुआ और सम्मान भी हुआ जिसने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का कद तो बढ़ाया ही है साथ ही देश के संविधान में वर्णित संघीय स्वरूप को भी प्रतिष्ठा दी।

यद्यपि उनके उपवास का आशय केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के अनेक मुद्दों की निरंतर अनदेखी और हालिया पाला से पीड़ित प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिये मांगे गये 2440 करोड़ रूपये के पैकेज को अब तक स्वीकृति न देने के विरोध स्वरूप धरना था। फिर भी उन्होंने अपने उपवास को धरना नाम नहीं दिया। श्री शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में एक संवैधानिक पद पर हैं और धरना शब्द एक नकारात्मक संदेश देने लगा था। शिवराजसिंह चौहान का उद्देश्य चूंकि सकारात्मक था और वे संवैधानिक मर्यादा का उदाहरण भी देना चाहते थे। इसीलिये उन्होंने अपने उपवास को ''सविनय आग्रह उपवास'' का नाम दिया। साथ ही अपने सभी सहयोगियों को यह संदेश भी दिया कोई नकारात्मक बात न हो, नकारात्मक नारे न लगाए जाएं। केवल अपनी बात कही जाए और अपना आग्रह केन्द्र सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। अपनी इसी धारणा के कारण ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह की उस चिट्ठी का कोई उत्तर नहीं दिया जिसमें श्री सिंह ने इस उपवास को नौटंकी करार दिया था और व्यंगात्मक लहजे में पूछा था कि भाजपा का कौनसा नेता रस पिलाकर अनशन तुड़वाने आयेगा। निःसंदेह इस अवसर और स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी टिप्पणी न तो गरिमापूर्ण मानी जा सकती है और न किसानों के दर्द को कम कर सकती है। हास्य व्यंग जीवन के लिये जरूरी हो सकते हैं किंतु उनका प्रयोग अवसर, स्थान और पात्र देखकर किया जाना चाहिये। यह अवसर न तो ऐसे व्यंग का था और न उसका उत्तर देना ही उचित था। उम्र और अनुभव से कम होने के बावजूद श्री शिवराजसिंह ने शांत रहकर श्री दिग्विजय सिंह की तुलना में अपना कद बढ़ा लिया। एक तरफ जहाँ श्री दिग्विजय सिंह व्यंग कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर ने अपनी ओर से पहल की। वे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया हैं। इस नाते किसानों की समस्या से वे भी अवगत थे। उन्होंने अपनी ओर से केन्द्र सरकार से बात की और प्रधानमंत्री के सामने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। राज्यपाल ने फिर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान से बात की। प्रश्न इस बात का नहीं है कि केन्द्र सरकार श्री शिवराजसिंह की कितनी बातों से सहमत होती है और कितनी राहत मंजूर करती है लेकिन लगता है कि राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर सैद्धांतिक रूप में मध्यप्रदेश के किसानों के दर्द और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह के तर्कों से सहमत थे। इसलिये उन्होंने पहल की और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्री की फोन पर चर्चा करवाकर अपना सविनय आग्रह उपवास स्थगित करने का आग्रह किया। सद्भाव और सौजन्य का निर्वाह देखिये कि प्रधानमंत्री ने चर्चा के बाद मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा।

राजनीति में विचारों की भिन्नता, सिद्धांतों का विमेय अथवा दलीय हितों की प्राथमिकता पृथक हो सकती है फिर भी महत्वपूर्ण जनता होती हैं, जनता के लिये बनाया गया संविधान होता है। संघीय प्रणाली में एक सिरे पर यदि प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे सिरे पर मुख्यमंत्री होते हैं जो प्रणाली को मजबूत करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे किस राजनैतिक दल से संबंधित हैं। ताजा घटनाक्रम में राजनैतिक सीमाएं जनहित के सामने कमजोर पड़ी हैं और संविधान का संघीय स्वरूप एक नई परम्परा लेकर सामने आया है। इस घटनाक्रम में प्रशंसा की पात्र तीनों विभूतियां हैं राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)